खनन सुधार में प्रदेश नंबर-1 पर, केंद्र से मिले 100 करोड़

मुख्य संवाददाता, देहरादून

अमृत विचार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन और लगातार सुधारों के चलते उत्तराखंड एक बार फिर केंद्र सरकार से बड़ी प्रोत्साहन राशि हासिल करने में सफल रहा है। केंद्र के खान मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना के तहत उत्तराखंड को माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स में 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। इससे पहले भी अक्टूबर में राज्य को एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त होने पर 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। इस प्रकार खनन क्षेत्र में उत्कृष्ट सुधारों और बेहतर नीतियों की बदौलत उत्तराखंड को 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो चुकी है।

राज्य ने हाल के वर्षों में खनन सुधारों पर जोर देते हुए बेहतर नीतियां लागू की हैं, जिसका परिणाम यह है कि उत्तराखंड ने खनन सेक्टर में देश में नंबर-1 स्थान हासिल किया है। केंद्र द्वारा जारी सूचना के अनुसार, उत्तराखंड राज्य ने खनन क्षेत्र से जुड़ी अधिकांश सुधारात्मक कार्यवाहियों को समय पर और प्रभावी ढंग से लागू किया है। खासतौर पर माइनर मिनरल रिफॉर्म्स से संबंधित 7 में से 6 प्रमुख सुधारों के मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिससे राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

खनन क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी और व्यवसाय-हितैषी नीतियों ने सरकार की आय में अभूतपूर्व वृद्धि की है। खनन विभाग के सुदृढ़ प्रबंधन तथा नई नीतियों ने न केवल सरकारी खजाने को मजबूती दी है, बल्कि प्रदेश में खनन कारोबार से लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है और इससे जुड़े लाखों व्यापारियों और उद्यमियों को भी आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है।

स्थानीय लोगों और सरकारी कार्यदायी संस्था को सस्ते दाम पर निर्माण सामग्री मिल रही है। खनन गतिविधियों के चलते राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिली है।

> प्रदेश में खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई-नीलामी प्रणाली, सैटेलाइट आधारित निगरानी जैसे कई कदम उठाए गए हैं। सरकार पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, अवैध खनन पर लगाम कस रही है जिसके सकारात्मक परिणाम नजर आने लगे हैं।
> -पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

प्रदर्शन के आधार पर मिली रकम

केंद्र सरकार ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि उत्तराखंड खनन क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है और सुधारों को तेजी से लागू कर रहा है। इसी प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र ने वित्त मंत्रालय से राज्य को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में शामिल राज्यों- नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में उत्तराखंड का प्रदर्शन सबसे बेहतर दर्ज किया गया है। मंत्रालय के आदेश के अनुसार, सभी राज्यों ने खनन में सुधार प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनाई गई है।

राजस्व का एक मुख्य स्रोत

इस उपलब्धि के साथ यह साफ हो गया है कि उत्तराखंड का खनन क्षेत्र राज्य सरकार के लिए राजस्व का एक मुख्य स्रोत साबित हो रहा है। बढ़ती पारदर्शिता, बेहतर नीति निर्माण और समयबद्ध सुधारों की वजह से उत्तराखंड अब देश के खनन परिदृश्य में एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान बना रहा है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर आदि राज्य भी उत्तराखंड की खनन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं।

...तो परिणाम मिलते ही हैं

जब काम दमदार हो और नीयत साफ हो...तो परिणाम मिलते ही हैं। खनन के क्षेत्र में पीएसडी सरकार के सुधारात्मक प्रयास अब असर दिखाने लगे हैं। पहले के वर्षों में खनन से जितना राजस्व आता था, अब इस सरकार में उतने के तो केवल पुरस्कार ही लेकर आ रहे हैं। राज्य सरकार के प्रयासों और अवैध खनन व चोरी पर रोक के चलते खनन से प्राप्त होने वाले राजस्व में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पहले के 400-500 करोड़ रुपये के मुकाबले बीते साल में खनन से 1100 करोड़ से अधिक के राजस्व की प्राप्ति हुई है। सूत्रों के अनुसार, विशेषकर खनन को लेकर राज्य के कुछ चुनिंदा विघ्नसंतोषी लोग हमेशा एक नकारात्मक माहौल बनाकर रखते हैं जबकि ऐसे विघ्नसंतोषी लोगों की सरकारों में राजस्व रसातल में रहता था और अवैध कारोबार अपने चरम पर। मुख्यमंत्री धामी ने बीते वर्षों में अपने कड़े कदमों से यह सुनिश्चित किया कि प्रदेश के तमाम विभाग केवल कमाने-खाने का जरिया भर नहीं हैं, बल्कि इन विभागों की व्यवस्थाओं और तमाम प्रक्रियाओं में सुधार करके राज्यहित में कितना महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त किया जा सकता है। एक ऐसे राज्य में जहां पर राजस्व प्राप्ति के स्रोत कम हों, वहां अपने 'जीरो लीकेज' के संकल्प के बूते पहले तो राजस्व में गुणात्मक वृद्धि करना, फिर सैकड़ों करोड़ के पुरस्कार केंद्र से लेकर आना, राज्य के नेतृत्व के प्रबंधन और दूरदर्शिता को दर्शाता है।